Peoples Chin ke arthik sanbandon ke pehlu par ak charcha

पीपुल्स चीन के आर्थिक संबधों के पहलू पर एक चर्चा

यह बात-चीत हाल ही में फेसबुक के 'इन डिफेंस ऑफ स्टालिन' पर चली है. चीन के राजनीतिक अर्थशास्त्र से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे सवालो, जिनकी चर्चा और कँही नही की गई है, के जबाव के बतौर फिर से इसे यहाँ रखा जा रहा है.

बी. आर -: स्टालिन के अंदर सचमुच समाजवाद आर्थिक तौर पर काँफी दूर निकल चूका था. हाँलाकि राजनीतिक मायने में चीन का समाजवाद कहीं ज्यादा विकसित था. 60 के अंत में, प्रबंधक के पद से पूंजीपतियों के संपत्ति हरण और पदावनत करने की प्रक्रिया शुरु की जा चुकी थी. समूहिकीकरण और कम्युन का निर्माण भी शुरु किया गया था. इतिहास में पहली बार, अवाम समाजवादी समाज के भीतर वर्ग संघर्ष की जमीन पर आई और पार्टी के भीतर पूंजीवादी पथगामियों की पहचान की गयी. आखिरकार इंकलाब की हार हुई, लेकीन हार से पहले का दशक इतिहास में किसी भी समाजवादी शासन में सबसे उँचे राजनीतिक विकास की छाप लिए हुए हैं.

विएस: मै इससे पूरे तौर पर असहमत हुँ. स्टालिन ने ऐसे समाजवाद का निर्माण किया जो लेनिन के मौत के वक्त सोवियत यूनियन मे मौजूद समाजवाद से *गुणात्मक तौर पर उच्चतर था*. मै इस बात पर जोर दे रहा हुँ कि स्टालिन के रहते ही सोवियत यूनीयन एक मात्र अहम देश था जिसने हकीकत में समाजवाद का निर्माण किया. समाजवाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही और सभी उत्पादन के साधनो के समाजीकरण की माँग करता है. क्या यह पीआरसी(चीन) मे किया गया था? जैसा कि यह जानी हुई बात है कि 1949 में पीआरसी जनता का जनवादी राज्य था. इसने सही तौर पर एक साम्रज्यवाद विरोधी और सांमतवाद विरोधी राज्य को कायम किया था और सही तौर पर मध्य दर्जे के बुर्जुआजी से गठबंधन किया जो राज्य संरचना का हिस्सा और अंग था. ऐसा लगता है कि सीपसी के इस रुख से स्टालिन आश्वस्त थें. पीआरसी ने 1949 से 1952 के बीच साम्रज्यवाद विरोधी और सांमतवाद विरोधी इंकलाब को मुकम्मल किया और समाजवाद के कार्यक्रम पर आगे बढ़ना शुरू किया. यह एक ऐसे राज्य को कायम करने की माँग करता था जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के काम को अंजाम दे, इसका मतलब था कि राष्ट्रीय बुर्जुआ को जनता के राष्टीय कंग्रेस से बाहर निकाल फेंकना. इसे कभी भी अंजाम नही दिया गया. राज्य संरचना हमेशा इंकलाबी जनवाद के स्तर पर ठहरी रही. 1949 के बाद सीपसी द्वारा उत्तरी चीन में मार्क्स और एंगेल्स के मॉडल पर समुहीकीकरण की शुराआत की गई. गरीब और

मध्यम किसानो के सामुहिक फार्म बानाए गए और मशीन ट्रेक्टर स्टेशन को कायम किया गया जो कृषी संबधी उत्पादन के साधनो का मालिकाना हक रखती थी.

लेकीन 1953 के बाद एक विप्लवी बदलाब ने जगह ली. धनी किसानो को अब सामुहिक फार्म मे शामील किया गया. और 1958 के बाद मशीन ट्रेक्टर स्टेशन को खत्म कर दिया गया और जनता के कम्यून के हाथो मे दे दिया गया. यह मार्क्स और एंगेल्स के सिधांतो के खिलाफ था. अब यह जरुरी तौर पर कहना चाहिए कि चीन में कभी भी कम्युन का निर्माण नही किया गया, वहाँ के 'पीपुल्स कम्युन' में शहर और गाँव के राष्ट्रीय बुर्जाआ जी, पहले के जमींदार , कूलक और मेहनतकश अवाम और गरीब और मध्यम दर्जे के किसान से लोगो का शामील किया गया. जिस तरह से युएसएसआर में उत्पादन के साधनो का पूरे तौर पर सामाजीकरण किया गया, क्या कभी भी पीआरसी मे पुरी तरह से इसे लागू किया गया? नहीं. 1949 में बड़े उद्धोग का कुछ हद तक राष्ट्रीयकरण किया गया. लेकीन राष्ट्रीय बुर्जुआजी की संपत्ती कभी भी जब्त नही की गयी. जिसे 'समाजवाद' कहा गया, उसके भीतर संयुक्त राज्य-निजी उद्दमो के जरीए उनपर कुछ प्रतिबंध कायम किया गया. सांसकृतिक क्रांति में सुनिश्चित की गई सुद अदा की गई, और इसके खात्मे की शुरुआत फिर से की गई. पीपुल्स कम्युन उत्पादन के साधनो पर मालिकाना हक रखतें थें, ना केवल यह कृषी के उत्पादन के साधनो पर बल्कि उद्धोग निर्मित साधनो (स्टील वर्क , स्टीमशीप कंपनी) पर भी यह हक रखता था. इसका मतलब है, जैसाकि सोवियत संघ में था, उत्पादन के साधनो का पूरी तरह से सामाजीकरण कभी नही हुआ. पीपुल्स चीन के भीतर माल उत्पादन का क्षेत्र आनुपातिक तौर पर सोवियत यूनियन से बड़ा था.

सीपीसी अर्थव्यवस्था के भीतर बड़ी सी बड़ी तरक्की हमेशा एक बहुत ही उन्नत जनवादी अर्थव्यवस्था तक ठहरी रही, लेकिन जो कभी भी हकीकत में समाजवाद मे अपनी तब्दिली को मुकम्मल नही कर सकी. जबकि सोवियत रुस स्टालिन के वक्त अहम तौर पर एक समाजवादी देश था. यह साफ तौर पर कहा जाना चाहिये कि यह बात पीपुल्स चाइना के बारे मे नही कही जा सकती. पीआरसी में राष्ट्रीय बुर्जुआ जी पर सभी तरह के रोक-टोक के बावजुद यह नही कहा जा सकता कि : '60 के अंत में, प्रबंधको के पद से बुर्जुआजी की जब्ती और पदावनोत्ती की प्रक्रिया की शुराआत हो गई थी.' यें वर्ग आज तक बने हुए हैं. पीआरसी के भीतर बड़े पैमाने पर संघर्षों के बावजुद ऐसे राज्य की गैर मौजुदगी के चलते जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का काम और समाजवाद के निर्माण का काम मुकम्मल करता हो, यह दावा करना गलत है कि पीआरसी एक समाजवादी राज्य था. निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही या पूर्ण समाजवाद की अनुपस्थिति में 'समाजवादी समाज' में 'राजनीतिक विकास का उच्चतम स्तर' था. ऐसा मालुम पड़ता है कि सीपीसी के किसी भी हिस्से ने मेहनतकश अवाम के आगे जनता के जनवादी तानाशाही से सर्वहारा की

तानाशाही में तब्दिली का या पीआरसी में उत्पादन के साधनो का पूरे तौर पर सामाजीकरण का कभी सवाल ही नही रखा. सीपीसी का यह गैर मार्क्सवादी नजरिया जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक वियतनाम और डेमोक्रेटिक कोरिया के लिए प्रेरणा के स्त्रोत बने.

बी.आर.: मैं सोंचता हुँ आप कुछ बिन्दुओं पर गलत जा रहे है. बहुत सारे कारखाने राष्ट्रीय बुर्जुआजी से ले लिए गए थे, और उन्हे राज्य के नियत्रंण में रखा गया था. वे ब्याज अदा करतें थे, लेकिन यें ब्याज 60 के दशक में बंद कर दिया गया था. यह जब्ती के बराबर था. 1958 मे भी कम्युन के साथ जुड़े हुए समूह (और वे भी जो इस कम्युन के साथ नहीं जुड़े हुए थे) जमीन के निजी स्वामित्व के बदले सामुहिकता को अपनाया था. इसका मतलब इससे जुड़ने वाला किसी भी धनी किसान को अपनी जमीन समूह के हवाले कर देना होता था. इसका मतलब जहाँ तक जमीन पर मालिकाना हक की बात आती है वह धनी किसान नही रह गया था.

दरअसल , सबसे पहली चीज जो देंग ने की थी वो थी सामुहिकता को सक्रिय तौर पर तोड़ देना और जमीन की निजी मलकीयत को फ़िर से लागु करना.

वीएस.: कोई भी कारखाना राष्ट्रीय बुर्जुआजी से नहीं लिया गया था (देखे कुअन ता तुन्ग की कीताब). राष्ट्रीय बुर्जुआजी ने जनवादी राज्य के साथ स्युंक्त राज्य-निजी उद्दम कायम किया था जिसमे 5% ब्याज तय किया गया था. राष्ट्रीय बुर्जुआजी ने कारखाना प्रबंधन को चलाना जारी रखा. यह नई आर्थिक संरचना राज्य संरचना के अनुकुल थी जहाँ उन हालातों में जब पीआरसी की एक समाजवादी राज्य के बतौर घोषणा की गई सर्वहारा की तानाशाही का कोई वजुद नही था. हाँ, जैसे के पहले कहा गया है सासंकृतिक क्रातिं में सुद को बर्खास्त कर दिया गया. यह जब्ती की व्यख्या नहीं है हालाकि यह जब्ती की ओर बढ़ाया गया एक कदम था. सीपीसी ने समाजवाद के अंदर राष्ट्रीय पूँजी का राष्ट्रीयकरण करने की अपनी प्रतिबधता से अपने कदम वापस खींच लिए. अवश्य ही धनी किसान या जमीनदारों ने सामुहिक फार्मो या पीपूल्स कम्युन में जाने से पहले अपने जमीन को सुपुर्द किया लेकिन तब इन संस्थाओं का वर्ग आधार सोवियत सामुहिक फार्म से अलग था जो मार्क्स एगेंल्स के नजरीये को सख्ती से लागु करता था. इसका मतलब था कि सीपसी के नजरीए से सोवियत यूनीयन का अंतिम पुंजीवादी वर्ग को (और जमीनदार को) सामुहिक फार्मो से निकालना गलत था कि और मार्क्स तथा एंगेल्स इस बात में गलत थें कि उन्होने कम्यून का आधार (केवल) गरीब और मध्य दर्जे के किसान को बतलाया था. इसका यह भी मतलब होगा कि मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, और स्टालिन का यह कहना गलत था कि सामुहिक फार्म/ कम्यून को उत्पादन के साधन का स्वामित्व नही रखना चाहिए.

हाँ 1958 से पीपुल्स कम्युन जैसा यह सीपीसी द्वारा कहा जाता है (* कम्युन न कहे जैसा की आपने कहा है) जमीन की 'सामुहिक' मलकियत को अपना रहे थें. कृपया शहरी और ग्रामीण 'सामुहिक' कम्यून के बहु-वर्गीय चरीत्र को ध्यान मे रखे. लेकिन जनता के यह कम्युन भी कृषी से जुड़े उत्पादन साधनो और जनता के इन कम्युनो मे चल रहे उद्दोग जो युएसएसआर की तुलना मे कही अधीक बड़े पैमाने पर मालो के उत्पादन को पेश करता था पर अपना मलकीयत रखता था. आपको यह तय करना होगा कि राजनीतिक अर्थशास्त्र पर आप मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन और स्टालिन के साथ हैं या सीपीसी के साथ. आप जो भी तय करेंगे यह तथ्य बना रहेगा कि पीआरसी की अर्थव्यवस्था के व्यापक हिस्से का कभी भी सामाजीकरण ही नहीं हुआ और इसलिए वे कभी भी जनवादी अर्थव्यवस्था से परे जाकर समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ ही नही पाए. बेशक सभी कम्युनिस्टों को पीआरसी की लोकतांत्रिक उपलब्धियों का बचाव करना चाहिए वैसे ही जैसे वे लेनिन और स्टालिन के वक्त सोवियत युनियन की उपल्बधियों का बचाब करते हैं. देंग के सत्ता में आने के बाद माल-मुद्रा संबध का दूसरे चरण का विस्तार हुआ जिसे 'चार' के द्वारा विरोध किया गया था. ऐसा मालुम पड़ता है कि 1953 और 1958 के बीच सीपीसी के सभी अहम समुहों ने अपना समर्थन माल-मुद्रा को प्रसारीत करने वाली टीटोवादे-ख्रुश्चेववादी अर्थव्यवस्था को लागू करने में दिया .

रेवोलुशनरी डेमोक्रेसी, खंड XX, नंबर 1, अप्रैल, 2014

कुन्दन केडी द्वारा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित